



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1516]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2014/आषाढ़ 31, 1936

No. 1516]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2014/ASHADHA 31, 1936

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2014

का.आ. 1884(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में जारी करते हुए संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है कि एनपीपीए द्वारा जारी स्थायी आदेश सं. का.आ. 1730(अ) से 1779(अ), तारीख 10 जुलाई, 2014 में निर्धारित विनिर्मितियां किसी भी विनिर्माता जो कि डीपीसीओ, 2013 के तहत पैरा 2(n) के अन्तर्गत है, उक्त स्थायी आदेश में दी गई पैराग्राफ 12 के तहत दी गई सारणी के कॉलम सं. 5 में दी गई अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच नहीं सकता, जैसा भी मामला हो, अधिसूचित और निर्धारित उक्त स्थायी आदेशों में संबंधित अधिसूचना के संबंधित विनिर्मिति के संबंधित क्रम संख्या पर उक्त आदेशों में दी गई सारणी के कॉलम संख्या 5 के तहत निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य ऐसे सभी विनिर्माताओं पर जो कि निर्धारण अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर बेच रहे हैं, उन पर भी लागू होगी।

2. अधिकतम खुदरा मूल्य के निर्धारित स्थायी आदेश सं. का.आ. 1730(अ) से का.आ. 1779(अ) जो कि दिनांक 10.7.2014 को जारी किया गया था बाकी सभी निर्माता जो निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं, जो उपर्युक्त स्थायी आदेश के पैरा 12 में वर्णित नहीं है, उन सभी निर्माताओं को डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त आदेश के पैराग्राफ 25 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुसूची-II के फॉर्म V में दी गई मूल्य सूची को जारी करके लागू किया जाएगा।

3. डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बने रहेंगे, उसके पश्चात् उक्त आदेश के पैरा 20(1) के तहत खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक मूल्य वृद्धि अनुमत्य नहीं होगी।

4. उपर्युक्त पैरा 2 और 3 की असफलता/अनुपालन न होने की स्थिति में निर्माता/विपणन कम्पनी, अधिसूचना की तारीख और/या 10 प्रतिशत मूल्य संवर्धन की तारीख से जैसा भी मामला हो, अधिप्रभारित राशि ब्याज सहित जमा कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. उक्त विनिर्मितियों के लिए निर्माता/विपणन कम्पनी इस आदेश और इसमें उल्लेखित शर्तों के प्रति संयुक्त एवं गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे।

[कां. सं./148/2014/वि/फा. सं. 23(1)/2014/डिवी.-III/एनपीपीए]

इन्जेटी श्रीनिवास, अध्यक्ष

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICALS PRICING AUTHORITY)****ORDER**

New Delhi, the 22nd July, 2014

S.O. 1884(E).—In exercise of the powers, conferred by Paragraph 19 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) being satisfied that it is necessary so to do in the public interest hereby notifies that any manufacturer covered under paragraph 2(n) of the DPCO, 2013 selling formulation(s) at a price higher than the maximum retail price (MRP) notified in the column 5 of the table under paragraph 12 and not covered in the said paragraph of the standing orders Nos. 1730(E) to 1779(E) issued on 10.07.2014 by the NPPA, the MRP fixed and notified under column 5 of the above said table mentioned at the respective serial number of the respective formulation of the respective notification shall also be applicable to such manufacturer, as the case may be.

2. The MRP fixed vide standing order Nos. 1730 (E) to 1779 (E) issued on 10.07.2014 shall be implemented by all left out manufacturer who are selling at a price higher than the notified price, not mentioned in paragraph 12 of the above said orders as per the provision of the DPCO, 2013, by issuing a price list in Form V of Schedule-II in accordance with the provisions of paragraph 25 of the said order.

3. The MRP so fixed under paragraph 19 of DPCO, 2013 shall be maintained for a period of one year from the date of notification after which annual price increase not exceeding 10% of the maximum retail price will be permissible under paragraph 20 (1) of the said order.

4. In case of failure / non-compliance of para 2 and 3 above, the manufacturer/marketer shall be liable to deposit the overcharged amount alongwith the interest thereon from the date of notification and/or date of price increase beyond 10%, as the case may be.

5. The concerned manufacturer/marketing company shall be jointly and severally responsible to comply with this order and conditions mentioned herein above.

[PN/148/2014/F/F. No. 23(1)/2014/Div-III/NPPA]

INJETI SRINIVAS, Chairman